



2026:AHC:67555

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 11547 वर्ष 2026

जीतू @ जीतू कुमार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अमित कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 80

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आज दायर किए गए लघु जवाबी हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार यादव, विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता संख्या-2/सूचनाकर्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार यादव उपस्थित हैं।
3. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें केस अपराध संख्या-77 वर्ष 2024 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या-172 वर्ष 2024 (राज्य बनाम जीतू) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो पाँक्सो अधिनियम की धारा 3, 4(2) के तहत, थाना डाकोर, जिला जालौन के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांक 28.10.2024 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 29.10.2024 को ओराई में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो अधिनियम), जालौ की अदालत में लंबित है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और अन्य सह-आरोपी अरविंद और उदय भान को थाना-डाकोर, जिला जालौन की धारा 366 भ०द०वि० के तहत केस अपराध संख्या-77 वर्ष 2024 में आरोपी बनाया गया था। पीड़िता का बयान जांच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के दौरान दर्ज किया गया था जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसने इलाहाबाद में आवेदक के साथ अपनी शादी कर ली है और वह आवेदक के साथ रहना चाहती है। इसी तरह का बयान पीड़िता द्वारा तब दिया गया था जब उसे धारा 164 द०प्र०स० के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। उसने स्वीकार किया कि आवेदक के साथ उसका विवाह 15.08.2024 को हुआ था। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने एक आवेदन 528 बी.एन.एस.एस. संख्या-6202 वर्ष 2025 (अरविंद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) दायर किया था, जिसे इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था।

5. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों ने इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष 12.08.2025 को समझौता किया, हालांकि, आवेदक समझौता समझौते में पक्षकार नहीं था, लेकिन उसने 12.08.2025 के निपटान समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए और समझौता समझौते में यह उल्लेख किया गया है कि पीड़ित और आवेदक ने अपनी शादी कर ली है और वे सामंजस्यपूर्ण तरीके से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। पीड़िता ने आगे कहा कि आवेदक और पीड़ित के समझौते और विवाह को देखते हुए आवेदक के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ दिया जाए। सह-आरोपी अरविंद और उदय भान के खिलाफ कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या-6202 वर्ष 2025 के तहत आवेदन के तहत दिनांक 18.08.2025 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

6. आगे यह तर्क दिया जाता है कि उक्त समझौते के मद्देनजर, अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को **बी.एस. हरियाणा राज्य और अन्य, 2003(4) एस.सी.सी. 675, और जान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 (10) एस.सी.सी. 303** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में रद्द कर दिया जाए।

7. अपने तर्क के समर्थन में आवेदकों के अधिवक्ता ने **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466** में रिपोर्ट किए गए मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है, **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (2014) 9 एस.सी.सी. 653** और **परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एस.सी.सी. 641** में रिपोर्ट किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों और विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और इस तरह प्रतिपक्षी संख्या-2 आवेदकों के खिलाफ उपरोक्त मामले को दबाना नहीं चाहता है। विपक्षी पक्ष संख्या-2 आवेदकों के अभियोजन को वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते को देखते हुए, यदि अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. दूसरी ओर, राज्य के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2 और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को उपरोक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है। पीड़ित की ओर से दायर किए गए संक्षिप्त जवाबी हलफनामे में, पीड़ित द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक और पीड़िता के विवाह से 29.12.2025 को एक बच्ची का जन्म हुआ था और पीड़िता एक बड़ी लड़की थी जिसकी जन्मतिथि 01.01.2004 थी। लघु जवाबी हलफनामे में किए गए कथन को प्रमाणित करने के लिए पीड़ित के आधार कार्ड की एक प्रति और आवेदक और पीड़ित की बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लघु जवाबी हलफनामे में संलग्न किया गया है।

9. बी.एस. जोशी (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि पक्षों के बीच समझौते के तहत विवाद समाप्त हो गया है, तो धारा 320 भ०द०वि० के तहत निहित किसी भी बात के बावजूद, पक्षों के बीच दर्ज किए गए समझौते को देखते हुए अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत धारा 498-ए भ०द०वि० आदि की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस अदालत के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। जान सिंह (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-61 में कहा है कि;

"अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए एक आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक प्रचुरता की है जिसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी



न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती, आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद का निपटारा कर दिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई भी समझौता या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन भारी और मुख्य रूप से सिविल पक्ष वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षगण ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौता के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या



आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित होगा या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना है या नहीं, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।

10. राम गोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 118 एसीसी 318 (आपराधिक अपील संख्या-1488 वर्ष 2012) में हाल ही में एक फैसले में, 29.9.2021 को निर्णय दिया गया, में किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि भले ही अपराध गैर-शमनीय हों, उच्च न्यायालय अपराधों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराधों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीड़ित ने स्वेच्छा से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सहमति दी है। ऐसा करते हुए, यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय निर्विवाद रूप से किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराधों के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुंडागर्दी, भले ही दंडित न हो, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या पंगु नहीं बनाता है। उक्त निर्णय के प्रस्तर-14 में, सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: -

"14. दूसरे शब्दों में, गंभीर या गंभीर अपराध या अपराध जो नैतिक अधमता से जुड़े हैं या समाज के सामाजिक और नैतिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या सार्वजनिक नीति से संबंधित मामलों को शामिल करते हैं, को केवल दो व्यक्तियों या समूहों के बीच नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसे अपराधों में बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने की क्षमता होती है। रद्द करने की प्रक्रिया के माध्यम से घृणित अपराधों को नष्ट करने से न केवल समुदाय को एक गलत संकेत मिलेगा, बल्कि बेईमान आदतन या पेशेवर अपराधियों को भी अनुचित लाभ मिल सकता है, जो दबाव, धमकियों,



सामाजिक बहिष्कार, रिश्वत या अन्य संदिग्ध साधनों के माध्यम से 'समझौता' सुरक्षित कर सकते हैं। यह अच्छी तरह से कहा गया है कि "किसी भी दोषी व्यक्ति को भागने नहीं देना चाहिए, अगर इसे टाला जा सकता है।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (आपराधिक) संख्या-7212 वर्ष 2025 से उत्पन्न होने वाले मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के एक अन्य फैसले में, एसएलपी (आपराधिक) संख्या-7495 वर्ष 2025 से उत्पन्न होने वाले एसएलपी (आपराधिक) संख्या-7495 वर्ष 2025 से उत्पन्न मामले अपराध संख्या-302 वर्ष 2023, दिनांक 20.11.2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया, साथ ही पक्षों के बीच समझौते के आधार पर धारा 376, 354-ए, 354-डी, 509 और 506 के तहत मामला अपराध संख्या-304 वर्ष 2023, दिनांक 21.11.2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के प्रस्तर-6, 7 और 8 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"6. शुरुआत में, हम मानते हैं कि धारा 376 भ०द०वि० के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। आमतौर पर, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने से हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 द०प्र०स० के तहत न्यायालय की शक्ति एक कठोर सूत्र द्वारा विवश नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. प्रस्तुत मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां भ०द०वि० की धारा 376 सहित गंभीर आरोपों को लागू करने वाली प्राथमिकी प्रतिपक्षी द्वारा दर्ज की गई पहले की प्राथमिकी के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ देता है और सुझाव देता है कि दूसरी प्राथमिकी एक प्रतिक्रियावादी कदम हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उसने प्रस्तुत किया है कि वह अब शादीशुदा है, अपने निजी जीवन में बस गई है, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उसकी शांति और स्थिरता ही भंग होगी। उसका रुख



न तो अस्थायी है और न ही अस्पष्ट, उसने अभिलेखों पर एक हलफनामे सहित लगातार कहा है कि वह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करती है और चाहती है कि मामला समाप्त हो जाए। पक्षगण ने भी अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और आपसी समझ पर पहुंच गए हैं। इन परिस्थितियों में, मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह केवल सभी संबंधितों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए संकट को लम्बा खींचेगा, और उत्पादक परिणाम की संभावना के बिना अदालतों पर बोझ डालेगा।

8. इसलिए, इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्ट रुख और निपटान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

12. मैंने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों/आरोपों का अध्ययन किया है और मेरी राय है कि ये ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो उन मामलों के अपवाद वर्ग में आते हैं जहां कार्यवाही को रद्द करने और अभियुक्त को बिना सजा दिए जाने की अनुमति देने से बड़े पैमाने पर समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि पक्षों ने पहले ही अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, इसलिए आवेदकों को दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में, आवेदकों के खिलाफ आरोप निहित रूप से वापस ले लिए गए हैं और छोड़ दिए गए हैं, इसलिए, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम उरव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या-(एस) 41/2021, 10.01.2025 को निर्णय लिया गया, ने अपीलकर्ता को दोषसिद्धि के साथ-साथ इस आधार पर लगाई गई सजा को भी रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता/आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़ित ने एक-दूसरे से शादी की थी।

14. इसी तरह, दसारी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में (2024) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 936 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें समान परिस्थितियों और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगभग समान प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। दसारी श्रीकांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर-8 से 10 में निम्नानुसार पढ़ा गया है: -

"8. चूंकि, अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से शादी कर ली है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि का आरोपी अपीलकर्ता को जेल भेजे जाने पर विनाशकारी परिणाम होगा जो बदले में शिकायतकर्ता के साथ उसके वैवाहिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है।

9. परिणामस्वरूप, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अभियुक्त अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है।

10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 जून, 2023 के आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित 9 अप्रैल, 2021 के फैसले को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

15. प्रस्तुत मामले के तथ्य उपरोक्त निर्णयों से काफी मिलते-जुलते हैं। यहां भी मुझे लगता है कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसके अनुसार वह कथित अपराध की तारीख पर स्वेच्छा से आवेदक आरोपी के साथ गई थी। इसके बाद, उसने उससे शादी कर ली। इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376(3) के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है। पुलिस ने बिना सोचे-समझे यांत्रिक तरीके से आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है और दुर्भाग्य से विचारण न्यायालय ने भी इस मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। दूसरे, यहां सवाल उठता है कि क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376(3) के तहत आपराधिक मामले की कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 द०प्र०स० और 528 बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदन में रद्द किया जा सकता है, यदि पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया



हैं और लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में रह रहे हैं और विवाह से बच्चे का जन्म हुआ है।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस निरीक्षक द्वारा के. दंडपाणि बनाम राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1056 और मफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 433 के मामले में भी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आरोपी ने अभियोक्ता के साथ विवाह किया था और दूसरी बात, अदालत उक्त तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकती है। चूंकि के. दंडपाणि (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय छोटा है, इसलिए, इसे पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

"अनुमति दी गई।

अपीलकर्ता जो अभियोक्ता का मामा है, वलायार समुदाय से संबंधित है, जो तमिलनाडु राज्य में सबसे पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दैनिक मजदूरी पर लकड़हारे का काम करता है। उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चे का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 सपठित धारा 6, 5(i) सपठित धारा 6, 5(i) सपठित धारा 5(j)(ii) के तहत बलात्कार करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त अपराधों को करने के लिए मुकदमे के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया था और 31.10.2018 को सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय, तिरुपुर द्वारा 10 साल की अवधि के लिए कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के एक आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री एम.पी. पार्थिवन ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने उससे शादी करने के वादे पर अभियोक्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने कहा कि, वास्तव में, उन्होंने अभियोक्ता से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं।



अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और उसे पूर्ण न्याय करना चाहिए और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के पारिवारिक जीवन को परेशान करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है।

08 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभियोक्ता का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोक्ता का बयान अभिलेखों पर रखा गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं और अपीलकर्ता द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है और वह एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही है।

राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने अपीलकर्ता को इस आधार पर कोई राहत देने का विरोध किया कि अभियोक्ता अपराध की तारीख को 14 वर्ष की थी और उसने 15 वर्ष की आयु में पहले बच्चे को जन्म दिया था और जब वह 17 वर्ष की थी तब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच विवाह कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की कि उक्त विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से हो सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा उसे राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता अभियोक्ता और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित विचार है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा जो अभियोक्ता का मामा है, इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रद्द किया जाना चाहिए। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकता है और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन को परेशान नहीं कर सकता है। हमें तमिलनाडु में मामा के साथ लड़की की शादी की प्रथा के बारे में सूचित किया गया है।



उपरोक्त उल्लिखित कारणों से, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में अलग कर दिया जाता है और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा। यदि अपीलकर्ता अभियोक्ता की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या अभियोक्ता की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकता है।

17. मेरी सुविचारित राय में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376(3) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि पीड़िता ने उपरोक्त धाराओं के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि पीड़िता ने कभी भी यह नहीं कहा कि आवेदक द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376(3) के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए मूल घटक गायब है। तत्सम्य विपरीत, पीड़िता ने आवेदक के साथ विवाह किया है और विवाह से एक बच्ची का जन्म हुआ था और वे पिछले कई वर्षों से एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। यदि इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाता है, तो आवेदक और बच्चे के साथ पीड़ित को कानूनी चोट लग सकती है और आवेदक का मामला यहां ऊपर उल्लिखित मामलों से पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है।

18. यहां ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, प्रस्तुत आवेदन सफल होता है और इसकी अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है।

19. केस अपराध संख्या-77 वर्ष 2024 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या-172 वर्ष 2024 (राज्य बनाम जीतू) की पूरी कार्यवाही, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 4(2) के तहत, थाना डाकोर, जिला जालौन के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांक 28.10.2024 और 29.10.2024 के संज्ञान/समन आदेश, जो ओराई में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जालौ की अदालत में लंबित है, को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।



20. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

मार्च 31, 2026

ए.पी. पांडे

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.